

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 04/2006

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरौही ।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री हनुमान अग्रवाल पुत्र श्री सोहनलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी जैन भोजनशाला के पास, पत्थर गली, आबूरोड जिला सिरौही ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरौही ।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 03.05.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.2006 को जिला रसद अधिकारी सिरौही एवं उप अधीक्षक पुलिस आबूपर्वत के साथ माँ कृपा टेलिकॉम जैन भोजनशाला भवन के पास आबूरोड शहर की जांच करने पहुंचने पर वहां पर अलग-अलग कम्पनी के 15 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त 15 घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता ने जरिए वकालतनाम के उपस्थिति दी एवं जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 17.09.2006 को जिला रसद अधिकारी सिरौही एवं उप अधीक्षक पुलिस आबूपर्वत द्वारा माँ कृपा टेलिकॉम जैन भोजनशाला भवन के पास आबूरोड शहर की जांच करने पहुंचने पर वहां पर अलग-अलग कम्पनी के 15 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक विद्युत मोटर पाई गई। अप्रार्थी से पूछताछ करने पर अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग वाहनों में गैस भरने एवं बिना रसदी बुक के लोगों को देने में किया जाता है। गैस बत्ती अर्थात् पेट्रोमेक्स में गैस भरने तथा उपभोक्ताओं को अधिक कीमत पर विक्रय करने के काम में लिया जाता है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त 15 घरेलू गैस सिलेण्डर को निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरणों को जब्त सरकार किया जावे।



अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए गैस सिलेण्डर वापस दिलवाए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी

जिला कलेक्टर, सिरौही

द्वारा निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिए गए सभी गैस सिलेण्डर उनके द्वारा पेश की गई गैस डायरियों के उपभोक्ताओं के हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिए जाने से सभी उपभोक्ताओं को खाने बनाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कब्जे सरकार लिए गए सभी सिलेण्डर उनके मालिकी स्वामित्व के हैं जिन्हें उन्हें वापस दिया जाने का आदेश प्रदान करावें।

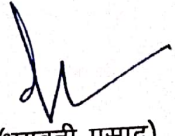
मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा 15 घरेलू गैस सिलेण्डरों 14. 2 किलो का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। जहाँ तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त सभी घरेलू गैस सिलेण्डर उनके द्वारा पेश की गई गैस डायरियों के उपभोक्ताओं के हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इसके सम्बन्ध में उनकी गैस डायरियां भी प्रस्तुत की गई हैं। चूँकि अप्रार्थी ने कब्जे सरकार लिए गए घरेलू गैस सिलेण्डरों की गैस डायरियां बाद में प्रस्तुत की हैं। अतः उक्त प्रकरण यह पता लगाना मुश्किल है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई गैस डायरियां कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की ही थीं।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी के विरुद्ध सद्भावनापूर्ण रुख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये 15 घरेलू गैस सिलेण्डरों को उनके मालिकी का होने से अप्रार्थी को स्थाई रूप से उन्हें लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा इनका उपयोग केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3/2 का उल्लंघन किया जाना नहीं पाया जाता है। जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी सिरौही को निर्देश दिए जाते हैं कि उपभोक्ताओं को दिए गए गैस सिलेण्डरों की रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत कर गैस कम्पनी से उपभोक्ताओं की डायरियों में अंकन कराकर फोटोकॉपी प्रस्तुत करें। चूँकि इस न्यायालय द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को जमानत/सुपूर्दगीनामे पर पूर्व में दिया जा चुका है। अतः अप्रार्थी द्वारा पेश की गई जमानत/सुपूर्दगीनामे को निरस्त किया जाता है। एवं जिला रसद अधिकारी सिरौही कब्जे सरकार ली गई विद्युत मोटर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार ली गई विद्युत मोटर को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2021 को खुले न्यायालय में डिकटेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।




(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही